Sale of drugs in Black Market

1045. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that costly drugs are being sold in the black market;

(b) if so, whether Government have conducted any inquiry in this regard, if so, the details thereof together with the names of the persons found guilty in this regard; and

(c) the action taken by Government to check the menace?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) No report regarding black-marketing of costly drugs have been received by the Government.

(b) and (c) Does not arise.

Scarcity of Molasses

1046. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether there is a severe scarcity of molasses in some states;

(b) if so, the position as on date; and

(c) the steps taken to remove the shortage of molasses?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) to (c) The prices and distribution of molasses were regulated under the Molasses Control Order, 1961 which was rescinded on 10th June, 1993 with a view to remove control on prices and distribution of molasses. After decontrol, the Government is not monitoring the production of molasses.

GAP' between Doctor Population Ratio

1047. SHRI K.M. SAIFULLAH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is a big gap between doctors and population ratio at present;

(b) if not, the facts thereof;

(c) the per head expenditure being spent on medical care activity at present; and

(d) the manner in which Government propose to achieve the goal of 'Health for AH' by 2000 A.D.?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) and (b) According to the Medical Council of India, the Doctor-Population Ratio in respect of allopathic doctors is about 1:1980. The ratio is far better than in other Countries of the South-East Asia Region. Taken together with the practitioners from the Indian Systems of medicine and Homoeopathy, the ratio is still better. However, disparities in the availability of Doctors exist in Rural Areas of some States, for which various measures have been initiated by individuals State Governments.

(c) As per information furnished by Central Statistical Organisation, per capita Government expenditure on Health, taken together with private consumption expenditure, comes to Rs.239/-. This figure is for 1995-96 at current prices and does not include expenditure incurred on Family Welfare, and directly by local authorities.

(d) To achieve the goal of "Health for AH", a wide network of rural health infrastructure comprising 136339 Sub-centres, 22010 Primary Health Centres, 2622 Community Health Centres administered by respective State GovernmentsLJT Administrations has been in operation throughout the country. External assistance has been

mobilised by the Central Government for supporting national programmes for control of diseases such as AIDS, Malaria, T.B., Leprosy and Blindness.

Secondary health facilities are also being upgraded in selected States with World Bank assistance.

Development of Indian systems of medicine and Homoeopathy is being encouraged to widen the network of health services available to the people. A comprehensive project for reproductive and child health caters to the special requirements of women and children.

आम बजट में नई परियोजनाओं की अनुमानित लागत

1048. **श्री अखिलेश दास :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) मंत्रालय के आम बजट में घोषित नई परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी-कितनी हैं;

(ख) उन नई परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं, जिनके लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है;

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या है, जिनके संदर्भ में अब तक पूर्ण रूप से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है, और

(घ) इन परियोजनाओं के लिए चालू बजट में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा0 ए0के0 पटेल) : (क) से (घ) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति विषयक संकल्प के अनुसार सामान्यत: नई उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है अत: नई उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उर्वरक विभाग द्वारा किसी प्रकार की तकनीकी मंजूरी दी जानी अपेक्षित नहीं है।

तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्राणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहाकारी सामितियों को अपनी प्रदत्त शक्तियों से आगे पूंजीगत व्यय करने से पूर्व सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना पडता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार निवेश अनुमोदन के लिए निम्नलिखित प्रमुख उर्वरक परियोजनाएं प्रस्तुत की गई है:-

(b) इफको : नेल्लोर, आन्ध्र प्रदेश में ग्रासरूट यूरिया संयंत्र।

(ii) कृभकों: गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में नया यूरिया संयंत्र (एफ सी आई के गोरखपुर संयंत्र की बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करके)

हजीरा, गुजरात स्थित संयंत्र की क्षमता में वृद्धि करने के लिए हजीरा चरणझ-॥ परियोजना।

(iii) आर सी एफ: थाल संयंत्र की यूरिया क्षमता का विस्तार।

(iv) एन एफ एल : पानीपत स्थित संयंत्र की यूरिया क्षमता का विस्तार।

चूंकि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है, अत: इनके लिए 1998-99 बजट में निधियों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निम्नलिखित परियोजनाएं वर्ष 1998-99 के लिए रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के बजट में सम्मिलित की गई है :-

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	नई परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
		(रू0 करोड़)
(I) इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कापोरेशन लि0	गंधार (गुजरात) में एक्रियोनिट्रायल का निर्माण	652.00
(II) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि0	(I) फीनोल एकक (कोचीन) का विस्तार	45.00
	(II) टैंक टर्मिनल (न्यू मंगलूर पोर्ट)	36.00
(III) हिन्दुस्तान इंसौक्टिसाइड्स लिमिटेड	दिल्ली एकक की अन्यत्र स्थापना	40.00

क्रम सं0 (i) और (ii) पर निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए विभाग के बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया